

अनुदान संख्या 38 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 38 - INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	229,07,00	225,13,62	-3,93,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-	5723,49,00	5645,88,82	-77,60,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			73,96,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	24,00,00		
		158,21,00	156,34,58	-1,86,42
पूरक	Supplementary	134,21,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"			
लेखा परीक्षा	Audit			
मू.	O.	572349.00		
		564953.00	564588.82	-364.18
पु.	R.	-7396.00		

(I) “सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय – केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति” के अंतर्गत – ₹19105.89 लाख बचत (₹23767.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण आईटी हार्डवेयर से फील्ड कार्यालयों को किए जाने, विक्रेता द्वारा “एक आईएएडी एक प्रणाली” परियोजना का हिस्सा पूरा न किए जाने और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) “रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय –फील्ड कार्यालय” के अंतर्गत – ₹703.32 लाख की बचत (₹29961.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹438.81 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) “सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय” –

(का) “सिविल लेखा कार्यालय” – ₹1198.97 लाख का अधिक व्यय (₹151958.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण आईटी हार्डवेयर से फील्ड कार्यालयों को किए जाने, आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रभारों में वृद्धि होने तथा अधिक दौरे किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “प्रशिक्षण” – ₹751.67 लाख का अधिक व्यय (₹7563.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण आईटी हार्डवेयर से फील्ड कार्यालयों को किए जाने, अधिक परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने, आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रभारों में वृद्धि होने तथा अधिक यात्रा भत्ते दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) “डाक और दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय” – ₹6309.61 लाख का अधिक व्यय (₹16815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बकाया जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, अधिप्राप्ति प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण आईटी हार्डवेयर से फील्ड

(I) Under “Civil Audit and Accounts Offices - Centralised Procurement” - saving of ₹19105.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23767.00 lakhs) was due to de-centralization of procurement process of IT hardware to field offices, non-completion of part of “One IAAD One System” project by vendor and delay in finalization of tender process.

(II) Under “Railway Audit Offices - Field Offices” - saving of ₹703.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29961.00 lakhs) was due to delay in finalization of tender process and recruitment process owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under one head saving of ₹438.81 lakhs occurred constituting 25 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following heads: -

(I) “Civil Audit and Accounts Offices” -

(A) “Civil Accounts Offices” - excess of ₹1198.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹151958.60 lakhs) was due to de-centralization of procurement process of IT hardware to field offices, increase in charges of outsourcing services and more tours undertaken.

(B) “Training” - excess of ₹751.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7563.00 lakhs) was due to de-centralization of procurement process of IT hardware to field offices, sanction of more projects, increase in charges of outsourcing services and receipt of more travelling allowance claims.

(II) “Posts and Telecommunications Audit Offices - Field Offices” - excess of ₹6309.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16815.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of arrears, de-centralization of procurement

कार्यालयों को किए जाने तथा अधिक चिकित्सा और यात्रा भत्ते दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(III) “रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय” – ₹1251.12 लाख का अधिक व्यय (₹13399.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने, अधिक यात्रा भत्ते दावे प्राप्त होने और अधिप्राप्ति प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण आईटी हार्डवेयर से फील्ड कार्यालयों को किए जाने के कारण हुआ।

(IV) “वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय” – ₹1660.53 लाख का अधिक व्यय (₹25431.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने, भवन किराया बकाया के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और अधिप्राप्ति प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण आईटी हार्डवेयर से फील्ड कार्यालयों को किए जाने के कारण हुआ।

(V) “समुद्रपारीय लेखापरीक्षा कार्यालय – फील्ड कार्यालय” – ₹914.10 लाख का अधिक व्यय (₹3415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश भत्ते, हवाई यातायात, होटल प्रभारों की दरों और लेखापरीक्षा संबंधी व्यय में वृद्धि होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹351.40 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

process of IT hardware to field offices and receipt of more medical and travelling allowance claims.

(III) “Defence Audit Offices - Field Offices” - excess of ₹1251.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13399.10 lakhs) was due to filling up of vacant posts, receipt of more travelling allowance claims and de-centralization of procurement process of IT hardware to field offices.

(IV) “Commercial Audit Offices - Field Offices” - excess of ₹1660.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25431.30 lakhs) was due to filling up of vacant posts, requirement of additional funds towards building rent arrears and de-centralization of procurement process of IT hardware to field offices.

(V) “Overseas Audit Offices - Field Offices” - excess of ₹914.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3415.00 lakhs) was due to increase in rates in foreign allowance, air traffics, hotel charges and audit related expenditure.

3. In the capital section of the grant, saving of ₹351.40 lakhs occurred under one head constituting 23 percent of the sanctioned provision.